नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 पूर्वी क्षेत्र भारत की विकास यात्रा का केंद्र

5 नेपाल में प्रदर्शनों के बीच सीमा पर कड़ी सुरक्षा

8 क्रिकेटर कपिल देव देंगे नेतृत्व और जीवन पर व्याख्यान

9 वाहन उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं : मोदी

अस्थायी पीएम के लिए मतभेद

नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए कार्की बनाम घिसिंग पर घमासान

काठमांडू, 11 सितंबर। नेपाल में जेन-जी युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इन झड़पों में अब तक 34 लोग मारे गए हैं और 1400 से अधिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगाए गए अल्पकालिक प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग में बदल गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद को भंग करने और संविधान में संशोधन की मांग की है।

प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद, अब देश का नेतृत्व करने के लिए अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा चल रही है। प्रदर्शनकारियों के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और पूर्व बिजली इंजीनियर कुलमान घिसिंग के नाम पर मतभेद सामने आए हैं।

प्रदर्शनकारियों के एक धड़े ने कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है, जबकि दूसरे गुट का कहना है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने के कारण वह संविधान के अनुसार पद नहीं संभाल सकतीं। इस असहमति के कारण प्रदर्शनकारी गुटों के बीच झड़पें भी हुई हैं। हालांकि, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने खुद नेतृत्व करने से इनकार करते हुए सुशीला कार्की का समर्थन किया है।

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी, क्योंकि उनके कार्यालय और आवास पर हुए हमले के बाद वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। इस बीच, नेपाली बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति से एक नागरिक सरकार बनाने और ताजा चुनाव कराने का आग्रह किया है।

भारत का रुख और बचाव कार्य

नेपाल में जारी अशांति के कारण भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार और आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सरकारें अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार और अपनी टीम को फंसे हुए तेलुगु लोगों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए धन्यवाद दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन शुरू की है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

दिल्ली समेत पूरे देश को दहलाने की साजिश

दिल्ली, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और झारखंड में हुई कुल 5 की गिरफ्तारी

नई दिल्ली 11 सितंबर (वार्ता) दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक खतरनाक आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो पाकिस्तान आधारित हैंडलर के निर्देश पर भारत में खिलाफत स्थापित करने और गजवा-ए-हिंद के तहत जिहाद छेड़ने की साजिश रच रहा था.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में छापेमारी कर पांच मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. इनकी पहचान अशहर दानिश (रांची), आफताब अंसारी (मुंबई), सुफियान अबुबकर खान (झारखंड), मोहम्मद हुजैफा यमन (तेलंगाना) और कामरान कुरैशी (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. इस ऑपरेशन में कुल 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से छह को राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार प्रशिक्षण लेते पकड़ा गया.

मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अशहर दानिश, जो रांची से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर है, वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था.

12 से अधिक स्थानों पर की छापेमारी

पुलिस ने दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद, राजगढ़ और पलामू सहित 12 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. बरामद डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच चल रही है, जिससे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया जा सके. केंद्रीय एजेंसियां, जिनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और खुफिया ब्यूरो (आईबी) शामिल हैं, इस साजिश की गहराई की जांच कर रही हैं.

एक नजर में

सोनिया गांधी पर मुकदमा दर्ज याचिका खारिज

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका गुरुवार खारिज कर दी. यह याचिका गांधी के कथित तौर पर भारत की नागरिकता लेने से करीब तीन साल पहले यहां की मतदाता सूची में नाम शामिल होने का आरोप से संबंधित है. इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी. राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा, हमने शिकायत खारिज कर दी है. अदालत ने विकास त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

तीन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने सिफारिश

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को पदोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाने की गुरुवार को सिफारिश की। शीर्ष अदालत की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी को उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।

मस्क फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने

नई दिल्ली। टेक दिग्गज एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज हासिल कर लिया। बुधवार को ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन उनसे आगे निकल गए थे, लेकिन चंद घंटे बाद ही कहानी बदल गई। इसके बाद मस्क अपने पहले पायदान पर वापस आ गए। एलन मस्क ने 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया था। इसके बाद से वे लगातार इस खिताब को बरकरार रखने में कामयाब रहे।

ट्रम्प के समर्थक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

वाशिंगटन. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धुर समर्थक एवं युवा कार्यकर्ता चार्ली किर्क की बुधवार को एक विश्वविद्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रखर युवा वक्ता चार्ली किर्क 31 वर्ष के थे और उटाह प्रांत में आरेम में उटाह वैली विवि में छात्रों की सभा को संबोधित कर रहे थे. हमलावर ने उन्हें गोली मार दी जो प्राण घातक सिद्ध हुयी. अधिकारियों ने कहा है कि हमलावर को पकड़ लिया गया है. राष्ट्रपति ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किर्क की हत्या को जघन्य बताते हुए इस घटना की निंदा की है. ट्रंप ने कहा कि उनके पास इस क्षति को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. उन्होंने कहा कि श्री चार्ली न केवल उनके लिए मित्र था, बल्कि वह भाई जैसा था.

ऐश्वर्या की निजता का अधिकार सुरक्षित

- नाम-तस्वीर के अनाधिकृत इस्तेमाल पर लगाई रोक
- एआई तकनीक से छवि के दुरुपयोग पर जताई चिंता

नई दिल्ली, 11 सितम्बर (वार्ता), दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीरों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह फैसला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करता है.

कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे बिना अनुमति के ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल न करें. कोर्ट ने कहा कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीकों का उपयोग कर उनकी छवि का गलत इस्तेमाल न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी ठेस पहुंचा रहा है. सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने बताया कि लोग उनकी तस्वीर, पसंद और नापसंद का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी छवि का उपयोग करके चीजें बेची जा रही हैं और यहां तक कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी परोसा जा रहा है.

अकोला दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुए दंगों के मामले की जांच के लिए गुरुवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए कहा कि एसआईटी में हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाएंगे. पीठ ने यह फैसला दंगों के दौरान हुई एक हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनाया. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया.

राष्ट्रपति के संदर्भ में फैसला सुरक्षित

राष्ट्रपति ने 14 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की मांगी थी राय

नई दिल्ली, 11 सितंबर (वार्ता). उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा निर्धारित करने के विवाद से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 10 दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे. राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह संदर्भ प्रस्तुत किया गया था, जो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख को किसी भी कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है. राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में 14 प्रश्नों पर शीर्ष अदालत की राय मांगी.

> सवालों में यह भी शामिल है कि क्या देश के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित है. संदर्भ में राय मांगी गई है. क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले, किसी भी रूप में, उसकी विषय-वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना अनुमन्य है?

छत्तीसगढ़ में 10 नक्सली ढेर

गरियाबंद में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन

टॉप कमांडर मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण मारा गया

गरियाबंद, 11 सितम्बर (वार्ता), छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली नेता मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण सहित कुल 10 नक्सलियों को मार गिराया है.

नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में मोडेम की मौत को सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. खुफिया जानकारी के आधार पर, जिसमें शीर्ष नक्सली नेता बालकृष्ण की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, बुधवार को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था. सुरक्षाबलों ने एक दूरस्थ क्षेत्र में नक्सलियों के एक समूह को घेर लिया. इस ऑपरेशन में राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन की टीमें शामिल थीं. मुठभेड़ के बाद, मारे गए नक्सलियों में मोडेम बालकृष्ण की पहचान की गई, जो ओडिशा स्टेट कमेटी का एक वरिष्ठ सदस्य था.

गरियाबंद जिला लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है. यहां सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हो चुकी हैं. सुरक्षाबलों ने नक्सलवाद को कमजोर करने के लिए कई सफल ऑपरेशन किए हैं.

पाकिस्तान में अलग-अलग अभियानों में 19 आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, 11 सितंबर (वार्ता). पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में तीन अलग-अलग अभियानों में 19 आतंकवादी मारे गए। सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के मोहमंद, उत्तरी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया। उन्होंने कहा मोहमंद में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जमकर हुई गोलीबारी में 14 आतंकवादी मारे गए।

12वीं में स्कूल के टॉपर 7832 बच्चों को मिली स्कूटी

- सीएम ने बच्चों को प्रतीकात्मक सौंपी स्कूटी की चाबी
- छात्रा हर्षिता की स्कूटी में सवार हुए मुख्यमंत्री

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को 12वीं में स्कूल के टॉपर बच्चों को स्कूटी की चावी सौंपी. पूरे प्रदेश में 7832 बच्चों को ये स्कूटी दी गई. भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से स्कूटी की चाबी सौंपी.

इस दौरान उन्होंने एक छात्रा, जिसे स्कूटी मिली, उनकी स्कूटी पर पीछे बैठकर सवारी भी की. इस दौरान सीएम और छात्रा दोनों ने ही हेलमेट भी पहन रखा था. बाद में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाशाली बच्चों से बाकायदा संवाद भी किया.

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 20 लाख से अधिक बालिकाओं को सैनिटेशन एवं हाइजीन के लिए 61 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी अंतरित की. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में विश्व में भारत का समय चल रहा है. प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं.

स्कूटी चलाने बच्चे लर्निंग लाइसेंस बनवाएं : सिंह

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आज विद्यार्थियों के लिए उत्सव का अवसर है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव सदैव बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं. स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी मिल रही है. स्कूटी चलाने के लिए बच्चे अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाएं और शिक्षकों व अभिभावकों के निर्देशों का पालन करें.

भागवत को 75वीं वर्षगांठ पर दी बधाई | **मॉरिशस को आर्थिक पैकेज देगा भारत**

भारत और मॉरिशस के सपने एक हैं : पीएम मोदी

वाराणसी 11 सितम्बर (वार्ता). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरिशस और भारत को एक परिवार करार देते हुए कहा है कि दोनों देशों के सपने एक हैं और भारत ने मॉरिशस की ढांचागत विकास तथा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए भी भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने मॉरिशस में आयुष उत्कृष्टता केन्द्र, 500 बिस्तर का सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल, वेटेनरी स्कूल और पशु अस्पताल के निर्माण सहयोग का भी निर्णय लिया है।

दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किएहैं। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने भी मॉरिशस विश्वविद्यालय के साथ समझौते किए हैं।

भागवत का जीवन समानता, समरसता के लिए समर्पित

नई दिल्ली, 11 सितम्बर (वार्ता). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को उनकी 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने कहा कि भागवत का पूरा जीवन सामाजिक समानता, समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है. मोदी ने देश और समाज के प्रति भागवत के सेवा कार्य का उल्लेख करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की. उन्होंने सोशल मीडिया पर दिए बधाई संदेश में कहा कि भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समाज को एकजुट करने में अपना जीवन समर्पित किया है.

उत्तराखंड को 1200 करोड़ की सहायता, पीएम ने की समीक्षा

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री ने किया दौरा
- मृतकों के परिवारों को 2 लाख की अनुग्रह राशि

देहरादून, 11 सितम्बर (वार्ता), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा कर राज्य में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की. देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर हुई बैठक में, प्रधानमंत्री ने राज्य के बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की. इसके साथ ही, हाल की बाढ़ और भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता का भी ऐलान किया गया.

पीएम मोदी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और सड़कों, स्कूलों और बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.